

UGC NET Paper 1 2012 june

www.Fillerform.info

Previous Years Solved Questions - UGC NET Paper 1 for July 201

Unit 3(Home work)Hindi/Eng-17 with ans

Read the following passage carefully and answer the questions 55 to 60 :

James Madison said, "A people who mean to be their own governors must arm themselves with power that knowledge gives." In India, the Official Secrets Act, 1923 was a convenient smokescreen to deny members of the public access to information. Public functioning has traditionally been shrouded in secrecy. But in a democracy in which people govern themselves, it is necessary to have more openness. In the maturing of our democracy, right to information is a major step forward; it enables citizens to participate fully in the decision-making process that affects their lives so profoundly. It is in this context that the address of the Prime Minister in the Lok Sabha is significant. He said, "I would only like to see that everyone, particularly our civil servants, should see the Bill in a positive spirit; not as a draconian law for paralyzing Government, but as an instrument for improving Government-Citizen interface resulting in a friendly, caring and effective Government functioning for the good of our People." He further said, "This is an innovative Bill, where there will be scope to review its functioning as we gain experience. Therefore, this is a piece of legislation, whose working will be kept under constant reviews."

The Commission, in its Report, has dealt with the application of the Right to Information in Executive, Legislature and Judiciary. The judiciary could be a pioneer in implementing the Act in letter and spirit because much of the work that the Judiciary does is open to public scrutiny, Government of India has sanctioned an e-governance project in the Judiciary for about ` 700 crores which would bring about systematic classification, standardization and categorization of records. This would help the judiciary to fulfil its mandate under the Act. Similar capacity building would be required in all other public authorities. The transformation from nontransparency to transparency and public accountability is the responsibility of all three organs of State.

55. A person gets power

(A) by acquiring knowledge

(B) from the Official Secrets Act, 1923

(C) through openings

(D) by denying public information

Answer: (A)

56. Right to Information is a major step forward to

(A) enable citizens to participate fully in the decision making process

(B) to make the people aware of the Act

(C) to gain knowledge of administration

(D) to make the people Government friendly

Answer: (A)

57. The Prime Minister considered the Bill

(A) to provide power to the civil servants

(B) as an instrument for improving Government-citizen interface resulting in a friendly, caring and effective Government

(C) a draconian law against the officials

(D) to check the harassment of the people

Answer: (B)

58. The Commission made the Bill effective by

(A) extending power to the executive authorities

(B) combining the executive and legislative power

(C) recognizing Judiciary a pioneer in implementing the act in letter and spirit

(D) educating the people before its implementation

Answer: (C)

59. The Prime Minister considered the Bill innovative and hoped that

- (A) It could be reviewed based on the experience gained on its functioning.
- (B) The civil servants would see the Bill in a positive spirit.
- (C) It would not be considered as a draconian law for paralyzing Government
- (D) All the above

Answer: (D)

60. The transparency and public accountability is the responsibility of three organs of the State.

These three organs are

- (A) Lok Sabha, Rajya Sabha and Judiciary
- (B) Lok Sabha, Rajya Sabha and Executive
- (C) Judiciary, Legislature and the Commission
- (D) Legislature, Executive and Judiciary

Answer: (D)

निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर 55 से 60 दें:

जेम्स मैडिसन ने कहा, "जो लोग अपने स्वयं के राज्यपाल होने का मतलब है कि ज्ञान के साथ खुद को शक्ति प्रदान करनी चाहिए।" भारत में, आधिकारिक राज अधिनियम, 1923 सार्वजनिक सूचना के सदस्यों को सूचना तक पहुंच से वंचित करने के लिए एक सुविधाजनक स्मोकस्क्रीन था। सार्वजनिक कामकाज पारंपरिक रूप से गोपनीयता में उलझा हुआ है। लेकिन एक ऐसे लोकतंत्र में जिसमें लोग खुद पर शासन करते हैं, अधिक खुलापन होना आवश्यक है। हमारे लोकतंत्र की परिपक्वता में, सूचना का अधिकार एक बड़ा कदम है; यह नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाता है जो उनके जीवन को इतनी गहराई से

प्रभावित करता है। यह इस संदर्भ में है कि लोकसभा में Prime मंत्री का पता महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, "मैं केवल यह देखना चाहूंगा कि सभी को, विशेषकर हमारे सिविल सेवकों को विधेयक को सकारात्मक भाव से देखना चाहिए; सरकार को पंगु बनाने के लिए ड्रैकियन कानून के रूप में नहीं, बल्कि सरकार-नागरिक इंटरफेस में सुधार के लिए एक साधन के रूप में जिसके परिणामस्वरूप हमारे लोगों की भलाई के लिए एक अनुकूल, देखभाल और प्रभावी सरकारी कामकाज हो। " उन्होंने आगे कहा, "यह एक अभिनव विधेयक है, जहां अनुभव प्राप्त करने के साथ ही इसके कामकाज की समीक्षा करने की गुंजाइश होगी। इसलिए, यह कानून का एक टुकड़ा है, जिसका काम निरंतर समीक्षाओं के तहत रखा जाएगा। "

आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कार्यकारी, विधायिका और न्यायपालिका में सूचना के अधिकार के आवेदन से निपटा है। न्यायपालिका पत्र और आत्मा में अधिनियम को लागू करने में अग्रणी हो सकता है क्योंकि काम है कि न्यायपालिका करता सार्वजनिक जांच के लिए खुला है की ज्यादा, भारत सरकार Judic में एक ई-शासन परियोजना की मंजूरी दी है मैं के बारे में के लिए 700 करोड़ जो अभिलेखों के व्यवस्थित वर्गीकरण, मानकीकरण और श्रेणीकरण के बारे में लाएगा। इससे न्यायपालिका को अधिनियम के तहत अपने जनादेश को पूरा करने में मदद मिलेगी। अन्य सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों में समान क्षमता निर्माण की आवश्यकता होगी। राज्य के तीनों अंगों के लिए पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही के लिए परिवर्तन से पारदर्शिता है।

55. एक व्यक्ति को शक्ति मिलती है

(ए) ज्ञान प्राप्त करके

(बी) आधिकारिक राज अधिनियम, १ ९ २३ से

(सी) उद्घाटन के माध्यम से

(घ) सार्वजनिक सूचनाओं का खंडन करके

उत्तर: (ए)

56. सूचना का अधिकार एक बड़ा कदम है

(ए) निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों को पूरी तरह से भाग लेने में सक्षम बनाता है

(ख) अधिनियम से लोगों को अवगत कराना

(ग) प्रशासन का ज्ञान प्राप्त करना

(घ) लोगों को सरकार के अनुकूल बनाने के लिए

उत्तर: (ए)

57. प्रधान मंत्री ने विधेयक पर विचार किया

(A) सिविल सेवकों को शक्ति प्रदान करना

(बी) सरकार-नागरिक इंटरफेस में सुधार के लिए एक उपकरण के रूप में, जिसके परिणामस्वरूप एक दोस्ताना, देखभाल और प्रभावी सरकार है

(ग) अधिकारियों के विरुद्ध एक कठोर कानून

(घ) लोगों के उत्पीड़न की जाँच करना

उत्तर: (बी)

58. आयोग ने विधेयक को प्रभावी बनाया

(ए) कार्यकारी अधिकारियों को शक्ति प्रदान करना

(बी) कार्यकारी और विधायी शक्ति का संयोजन

(सी) न्यायपालिका को पत्र और आत्मा में अधिनियम को लागू करने में अग्रणी के रूप में पहचानना

(डी) इसके कार्यान्वयन से पहले लोगों को शिक्षित करना

उत्तर: (सी)

59. प्रधान मंत्री ने विधेयक को अभिनव माना और आशा व्यक्त की

(ए) इसकी कार्यप्रणाली पर प्राप्त अनुभव के आधार पर इसकी समीक्षा की जा सकती है।

(बी) सिविल सेवक बिल को सकारात्मक भाव से देखेंगे।

(सी) यह paralyz के लिए एक कठोर कानून के रूप में नहीं माना जाएगा, मैं एनजी सरकार

(D) उपरोक्त सभी

उत्तर: (D)

60. पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही राज्य के तीन अंगों की जिम्मेदारी है।

ये तीन अंग हैं

(ए) लोकसभा, राज्यसभा और न्यायपालिका

(बी) लोकसभा, राज्यसभा और कार्यकारी

(ग) न्यायपालिका, विधायिका और आयोग

(घ) विधानमंडल, कार्यपालिका और न्यायपालिका

उत्तर: (D)